सोच
सकारात्मक हो
तो आपको सफलता
जरूर मिलेगी।
– अज्ञात

दुनिया से जो वादा किया

रिपोर्ट में कहा गया है कि 57 उच्च उत्सर्जन वाले देशों में से 31 के उत्सर्जन स्तर में कमी के रुझान दर्ज किए गए हैं। ये देश 90 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।

नवीन

भारत ने जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया से जो वादा किया, उसे निभाया भी है। इसी का नतीजा है कि इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) में पहली बार वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले दस देशों की सूची में शामिल हुआ है। इस सूची में पिछले साल भारत का मुकाम 11वां था, जो इस बार नौवां निकला है। हालांकि संतोष के लिए कोई जगह नहीं है। आदर्श स्थिति से अब भी हम बहुत दूर हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कॉप–25 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मंगलवार को जारी सीसीपीआई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग का मौजूदा स्तर 'उच्च श्रेणी' में नौवें स्थान पर है। इस अच्छी रेटिंग के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को जीवाश्म ईंधन पर दी जा रही सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करने की रूपरेखा बनानी होगी ताकि कोयले पर देश की निर्भरता कम हो सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि 57 उच्च उत्सर्जन वाले देशों में से 31 के उत्सर्जन स्तर में कमी के रुझान दर्ज किए गए हैं। ये देश 90 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।

अमेरिका की जगह इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन वाले देशों में है। अच्छे प्रदर्शन की दृष्टि से स्वीडन चौथे और डेनमार्क पांचवें स्थान पर है, जबकि पहले तीन स्थान खाली रखे गए हैं। इसका संदेश यह है कि दुनिया अभी भी निर्धारित लक्ष्य से बहुत दूर है। दुनिया में सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले चीन ने सूचकांक में अपनी रैंकिंग थोड़ी सुधारते हुए पिछले साल के 33वें के मुकाबले 30वां स्थान हासिल किया है। इससे एक बात तो तय है कि अमेरिका जैसे कुछेक अपवादों को छोड़कर सभी देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और सबने अपने–अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रयास जरूर किए हैं। पर दुनिया का आम नजरिया यही लगता है कि जब हालत बिगड़ेगी तो देखी जाएगी। यह रवैया कहीं महंगा न पड़ जाए। दरअसल यह संकट हमारी सोच से कहीं ज्यादा भयावह है और यह बिल्कुल हमारे सिर पर आ चुका है। कुछ महीने पहले ब्रिटेन के एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार ने कहा कि वह 'जलवायु परिवर्तन' के लिए कोई अलग शब्द इस्तेमाल करेगा ताकि इसकी भयावहता का अहसास हो। इसका नया नाम जलवायु आपातकाल, जलवायु संकट या किसी दुर्घटना और बाधा के कारण व्यवस्था का बैठ जाना, यानी ब्रेकडाउन हो सकता है। बहरहाल, हम इस बात पर संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि भारतीय प्रयासों को विश्व स्तर पर सराहना मिली है।

कॉप–25 सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के कदमों की चर्चा भी की, हालांकि अभी बहुत कुछ करना है। विश्व स्तर पर अपनी पहलकदमी जारी रखते हुए हमें अपने समूचे ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन रहित बनाने की ओर बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही मौसमों की अंधेरगर्दी से बचाव के लिए हमें अपने सुरक्षा जाल को भी मजबूत बनाना होगा।

गहरी नींद

मनमोहन। अच्छी परियां इस जादू को खत्म नहीं कर पायी लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इसके प्रभाव को कम कर दिया. उन्होंने कहा, "किसी नुकीली चीज के चुभने के बाद राजकुमारी की मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन वह सौ सालों तक के लिए गहरी नींद में चली जायेगी और यह तब ही जाग जायेगी जब कोई राजकुमार इसे ढूंढ़ लेगा. एक दिन राजकुमारी ने चरखे पर काम करने की कोशिश की, लेकिन चरखे का एक नुकीला हिस्सा उसकी उंगली पर चुभ गया. वह अचानक गिरकर बेहोश हो गई. शाही जोड़े ने राजकुमारी को वहां से उठाकर आरामदायक बिस्तर पर लिटा दिया जहां वह सौ सालों तक के लिए सो सके। जब तक हम इस बात से अंजान रहेंगे, तब तक हम सुसुप्ता अवस्था में हैं. हमारी आत्मा तभी जागृत होगी जब यह आंतरिक हिस्सों का अनुभव करेगी।

संपादकीय

उलटफेर के संकेत

दुनिया की सबसे बड़ी संसद यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव में उलटफेर के संकेत मिले हैं। अब तक आए परिणामों के अनुसार दक्षिणपंथी और वामपंथी पार्टियों के प्रति यूरोप में समर्थन कम हुआ है। 2014 में ऐसे रुझानों वाली पार्टियों को ज्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार 178 सीटों के साथ मध्य–दक्षिण रुझान वाली पार्टियों का समन्वय यूरोपियन पीपल्स पार्टी (ईपीपी) यूरोपीय संसद का सबसे बड़ा राजनीतिक समूह बनकर उभरी है। कहा जा रहा है कि इससे विचारों का टकराव कम तीखा होगा और सत्ता में संतुलन आएगा। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की दक्षिणपंथी क्रिश्चियन डेमोक्रेटस को 28 प्रतिशत मत मिले हैं, जो यूरोपीय चुनाव में उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। वामपंथी सहमेल सोशल डेमोक्रेट्स का प्रदर्शन भी बेहद कमजोर रहा है। उसे महज 16 प्रतिशत वोट मिल पाए हैं। ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन की विरोधी ब्रेग्जिट पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। इन चुनावों का भारतीय पक्ष यह है कि ब्रिटिश भारतीय उद्यमी दिनेश धमीजा लंदन से निर्वाचित हुए हैं। ब्रिटेन के ईयू में बने रहने के कट्टर समर्थक धमीजा ने लिबरल डेमोक्रेटिक सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उम्मीद से ज्यादा वोट पड़े हैं। माना जा रहा है कि इस बार युवा मतदाताओं ने कहीं ज्यादा उत्साह दिखाया है। यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपीय संघ का एकमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हिस्सा है। इसकी शुरुआत 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के रूप में छह यूरोपीय देशों की भागीदारी से हुई थी। यूरोपियन पार्लियामेंट लगभग समूचे यूरोप के लिए स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण, नौकरियां, वेतन और पारिवारिक मुद्दों पर कानून बनाती है।

मोदी ने स्पष्ट कहा कि चुनाव के दौरान चाहे जो भी बातें कही गई हों, उन सबका अब कोई महत्व नहीं है। बहुमत से सरकार चुनी जरूर जाती है पर चलती वह सर्वमत से है।

'सबका साथ, सबका विकास'

अनुप जोशी

चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग–अलग मौकों पर जो बातें कही हैं, उनका सार यह है कि एनडीए सरकार–2 की प्राथमिकता भारतीय संविधान की रोशनी में सबको साथ लेकर चलने की है। मोदी ने स्पष्ट कहा कि चुनाव के दौरान चाहे जो भी बातें कही गई हों, उन सबका अब कोई महत्व नहीं है। बहुमत से सरकार चुनी जरूर जाती है पर चलती वह सर्वमत से है। यानी मोदी अपने विरोधियों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, भले ही एक तबका इस जनादेश को 'हिंदू जनादेश' बताने की कोशिश करे। बीजेपी और एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ नए विचार दिए। पहला यह कि हमें 'सबका साथ, सबका विकास' करने के साथ सबका विश्वास भी हासिल करना है। जिन्होंने वोट दिया वे भी हमारे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वे भी हमारे हैं।

उन्होंने कहा कि 'कई दशकों तक अल्पसंख्यक समुदाय के मन में बीजेपी के प्रति एक डर का माहौल पैदा करके विरोधी पार्टियों ने उनका उपयोग वोट बैंक की तरह किया है। अब इन पांच वर्षों में हमारा लक्ष्य रहेगा काम के आधार

पर, संपर्क के आधार पर हर एक का विश्वास अर्जित करना, उनका दिल जीतना।' मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों ने अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा या बुनियादी सवालों पर कभी काम नहीं किया। सिर्फ डर का माहौल बनाकर उनके वोट लेने का काम किया। इसलिए आने वाले पांच साल में हमारा प्रमुख लक्ष्य उनका विश्वास पाना रहेगा। देश के अभिभावक के तौर पर मोदी ऐसा कह रहे हैं मगर क्या कुछ गुमराह लोगों की समझ भी उनकी सोच के अनुरूप ढल पाएगी? पिछले एक हफ्ते में देश के कई उत्तरी राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के आम लोगों पर हमले हुए हैं। इन दुखद घटनाओं के लिए किसी राजनीतिक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हमलावरों की कोई राजनीतिक पहचान नहीं पाई गई है।

लेकिन इन घटनाओं से जुड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जरूर चिंताजनक रही हैं। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद गौतम गंभीर ने प्रधानमंत्री के ही विचारों को आगे बढ़ाते हुए गुरुग्राम में एक अल्पसंख्यक युवक के साथ हुई बदसलूकी पर आपत्ति जताई तो उन्हें ट्रॉलिंग झेलनी पड़ी और अपनी ही पार्टी के लोगों के उलाहने सुनने पड़े। जरूरत यह सोच बदलने की है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की तरह इस बार भी अगर अल्पसंख्यकों पर हमले और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं दोहराई गईं तो देश का बहुत नुकसान होगा। भारत में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सेक्युलरिज्म का नारा बुलंद करने वाली तमाम पार्टियां जमीनी तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़ी हों, जो इधर लगातार खुद को अलग–थलग और असुरक्षित पा रहा है। ठीक है कि चुनावी हार के बाद से ये पार्टियां अंदरूनी उथल–पुथल की शिकार हैं। लेकिन सांगठनिक समस्याओं से निपटने के लिए उनके पास समय ही समय है। अभी उन्हें अपने जनाधार के साथ खड़े होकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

अष्टयोग-4894

7	4	5			6	1
	38		32		27	
	3		5	6		2
3	29	2	45	7	33	
1			7			4
	24	1	36	4	30	
6		4		2		3

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4893 का हल

5	1	3	6	7	2	4
6	34	6	33	1	33	7
7	5	1	3	6	4	2
1	29	2	31	4	31	5
2	4	7	5	3	6	1
3	30	4	37	5	33	6
4	1	5	6	2	7	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

बीजेपी के तारणहार दलों का क्षेत्रीय गणित

नरेंद्र नाथ। हाल के सालों में क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए संकटमोचक बन कर उभरे हैं। ताजा मिसाल नागरिकता संशोधन कानून है, जिसमें बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन वह इन्हीं क्षेत्रीय दलों की बदौलत इस बिल को पास कराने की उम्मीद कर रही है। बीजेपी की यह उम्मीद बेवजह नहीं है। तीन तलाक पर कानून बनाने की बात हो या अनुच्छेद 370 को हटाने की, मोदी सरकार इनके बूते ही सफलता पा सकी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये क्षेत्रीय दल अपने–अपने राज्यों में बीजेपी को लगातार राजनीतिक चुनौती दे रहे हैं तो आखिर क्यों बीजेपी उनके अजेंडे को बढ़ाने में उनकी मदद कर रही है? यह बात मानी हुई है कि क्षेत्रीय दल बीजेपी को जो समर्थन दे रहे हैं, उसके पीछे उनका अपना गणित है और वे अपने राजनीतिक नफे–नुकसान का हिसाब करके ही आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों की राजनीति देखें तो केंद्र में बीजेपी के राष्ट्रवादी और हिंदूवादी अजेंडे का साथ देने के बाद भी अपने–अपने राज्यों में ये दल क्षेत्रीय अस्मिता और लोकल मुद्दों पर बीजेपी को सियासी तौर पर कवर करते रहे हैं।